बाल विवाह में किसी भी रूप में शामिल सरकारी कर्मचारी पर कार्यवाही होगी

भजनलाल मंत्रिमंडल ने अशांत क्षेत्र में स्थायी निवासियों की संपत्तियों की रक्षा के लिए विधेयक को मंजूरी दी

जयपुर, 21 जनवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की सामाजिक संरचना, कानून व्यवस्था, औद्योगिक निवेश और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में अशांत घोषित क्षेत्रों में स्थायी निवासियों की संपत्तियों और किरायेदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक लाने, राजस्थान एयरोस्पेस एवं डिफेन्स पॉलिसी तथा राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी-2025 को मंजूरी देने सहित, अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी।

कैबिनेट बैठक के बाद उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने प्रेसवार्ता में निर्णयों की विस्तृत जानकारी दी। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 'दि राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इम्मूवेबल प्रोपर्टी एंड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेन्ट्स फ्रॉम एविक्शन फ्रॉम प्रिमाइसेज इन डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल, 2026' के प्रारूप को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि अशांत क्षेत्रों में दंगे और भीड़-हिंसा की स्थिति बनने पर वहां के स्थायी निवासी अपनी अचल संपत्तियां मजबूरी में कम दामों पर बेचने को विवश हो जाते हैं, जिससे क्षेत्र की सामाजिक संरचना और सामुदायिक सद्भाव प्रभावित होता है। उन्होंने बताया कि विधेयक लागू होने के बाद अशांत घोषित क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

- बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग में राजस्थान एयरोस्पेस व डिफैन्स पॉलिसी तथा राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी-2025 को मंजूरी देने का भी निर्णय लिया गया।

किसी भी प्रकार का अचल संपत्ति हस्तांतरण अमान्य और शून्य माना जाएगा। उल्लंघन करने पर अपराध को संज्ञेय और गैर-जमानती माना जाएगा, जिसमें दोषी को 3 से 5 वर्ष तक का कारावास और अर्थदंड का प्रावधान रहेगा। विधेयक को विधानसभा के आगामी सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे अशांत क्षेत्रों में स्थायी निवासियों और किरायेदारों के अधिकारों को कानूनी संरक्षण मिल सकेगा।

उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि राज्य को एयरोस्पेस और डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के उद्देश्य से राजस्थान एयरोस्पेस एवं डिफेन्स पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। यह नीति एमएसएमई, स्टार्टअप्स और नवाचार आधारित इकोसिस्टम को बढ़ावा देने पर केन्द्रित है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने राज्य की पहली राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी-2025 को भी मंजूरी दी है।

राज्य सरकार प्रशासनिक सुधारों की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। मंत्रिमंडल ने राजस्थान लोक सेवा आयोग में उप सचिव पदों के नामकरण में बदलाव और सहायक सचिव तथा निजी सचिव संवर्ग से उप सचिव पद पर पदोन्नति का अनुपात 10:1 करने का निर्णय लिया। इसके लिए संबंधित सेवा नियमों में संशोधन किया जाएगा। इसके साथ ही राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 में संशोधन कर बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 2006 के अनुरूप बालक की परिभाषा तय करने का निर्णय लिया गया है। अब 21 वर्ष से कम आयु का पुरुष और 18 वर्ष से कम आयु की महिला बालक माने जायेंगे और बाल विवाह में किसी भी रूप में शामिल सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि किसानों और पशुपालकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 23 जनवरी से प्रदेश भर में ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। ये शिविर दो चरणों में कुल 10 दिनों तक चलेंगे, जिनमें 2839 शिविर आयोजित होंगे।

'कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है या विदेशी, यह चुनाव आयोग तय नहीं कर सकता'

नई दिल्ली, 21 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की उस प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जिसमें आयोग ने कई राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू किया है। अदालत ने सीधा सवाल किया कि क्या आयोग इतने व्यापक अधिकार रखने के बावजूद किसी संदिग्ध नागरिक पर प्रारंभिक जांच भी नहीं कर सकता।

- एसआईआर पर चुनाव आयोग ने सख्त टिप्पणी की व कहा कि नागरिकता तय करना केन्द्र सरकार या विदेशी न्यायाधिकरण का काम है

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अगुवाई वाली पीठ ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि यदि मतदाता सूची को साफ-सुथरा रखना आयोग की जिम्मेदारी है, तो शुरुआती जांच उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर कैसे हो सकती है।

पीठ ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की, जिसमें आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग की यह एसआईआर प्रक्रिया लोगों पर नागरिकता साबित करने का अनावश्यक दबाव डाल रही है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, आयोग के अधिकारी यह तय नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति नागरिक है या विदेशी, क्योंकि यह अधिकार सिर्फ केन्द्र सरकार या विदेशी न्यायाधिकरण के पास है। अदालत ने इस पर पूछा कि यदि कोई नाम संदिग्ध लगे, तो क्या आयोग सिर्फ शंका दर्ज नहीं कर सकता और उसे संबंधित प्राधिकरण को भेज नहीं सकता।

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बुधवार को टोंक में एसआईआर की निगरानी में लगे कार्यकर्ताओं को सम्बोधित किया।

वोट का अधिकार छीनने की कोशिश को स्वीकार नहीं किया जाएगा- पायलट

सचिन पायलट ने टोंक में कांग्रेस पार्टी के बीएलए की मीटिंग में भाग लिया

- कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कार्यकर्ताओं से कहा कि जब तक मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन नहीं हो जाता, हमारा कार्य पूर्ण नहीं होगा। दस्तावेज़ के अभाव में किसी भी वैध मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं कटे, यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

टोंक, 21 जनवरी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं टोंक विधायक सचिन पायलट के एक दिवसीय टोंक दौरे पर रहे। सचिन पायलट का टोंक पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण में सतर्कता के लिए लगाये गये कांग्रेस पार्टी के बीएलए की बैठक को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह निर्वाचन आयोग का दायित्व है कि देश के प्रत्येक नागरिक के मताधिकार को सुरक्षित रखे। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे। आज देश में कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि राजनैतिक हित साधने के उद्देश्य से मतदाता सूचियों से सैकड़ों लोगों के नाम काटने या जोड़ने के लिए बी.एल.ओ. पर अनाश्यक दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे अनुचित दबाव के चलते कई स्थानों पर तो बी.एल.ओ. आत्महत्या जैसा कदम उठाने को भी मजबूर हो गये हैं। वोट देने का अधिकार हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और कोई इसे छीनना चाहेगा तो उसे कतई स्वीकार नहीं किया जायेगा।

पायलट ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा प्रमाण सहित उजागर की गई मतदाता सूचियों की गड़बड़ियों और बिहार चुनाव में निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली से साफ हो गया है कि निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता संदेह के घेरे में है। ऐसे में अपने मताधिकार की रक्षा के लिए हमें जागरूक रहना होगा। उन्होंने टोंक में लगे बी.एल.ए. के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि आपने एस.आई.आर. के कार्य में जो हिम्मत, हौसला, संयम और सजगता का परिचय दिया है, उसके लिए आप बधाई के पात्र है। उन्होंने कहा कि जब तक मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन नहीं हो जाता, तब तक हमारा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। दस्तावेज के अभाव में किसी भी वैध मतदाता का नाम मतदाता सूची से न कटे, यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

बैठक के दौरान पीसीसी सचिव सुमित गर्ग, नवनियुक्त कांग्रेस जिला अध्यक्ष सऊद सईदी, निवर्तमान जिला अध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा, पीसीसी उपाध्यक्ष रामविलास चौधरी एवं सभी बीएलए मौजूद रहे । इस दौरान एसआईआर के द्वितीय चरण को लेकर बीएलए की कार्यशाला का आयोजन हुआ। बैठक के बाद सचिन पायलट ने टोंक में पूर्व विधायक कमल बैरवा के नवीन प्रतिष्ठान होटल ओम साईं का उद्घाटन तथा पार्षद हरेन्द्र सांसी के नए पेट्रोल पंप का शुभारंभ किया।

विनोद तावड़े ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सामने आया है। हाल के वर्षों में तावड़े और माधव, दोनों ही भाजपा नेतृत्व की प्राथमिकता सूची से बाहर माने जा रहे थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्हें राजनीतिक जीवन की नई पारी दी गई है। तावड़े को केरल विधानसभा चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया गया है, साथ ही उन्हें चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए चुनाव पर्यवेक्षक की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। वहीं, राम माधव को ग्रेटर बेंगलुरु नगर निगम चुनावों का प्रभारी बनाया गया है। केरल जैसे पूर्ण विधानसभा चुनाव और तेलंगाना व बेंगलुरु के नगर निकाय चुनावों के लिए एक साथ नियुक्तियां कर नए पार्टी अध्यक्ष ने भाजपा की उस पुरानी नीति को फिर से रेखांकित किया है, जिसके तहत पार्टी किसी भी चुनाव को इतना छोटा नहीं मानती कि उस पर केन्द्रीय नेतृत्व द्वारा ध्यान न दिया जाए।

पूर्व महाराष्ट्र मंत्री विनोद तावड़े कई विवादों के चलते कभी नेतृत्व की पसंद तो कभी नापसंद बनते रहे है। उन पर महाराष्ट्र चुनावों के दौरान मतदाताओं में पैसा बांटने के आरोप लगे थे। विपक्ष ने उन पर महाराष्ट्र विधानसभा में फर्जी डिग्रियां जमा करने का भी आरोप लगाया है। 2019 में तावड़े उन वरिष्ठ भाजपा नेताओं में शामिल थे, जिन्हें हाशिये पर डाल दिया गया था। लेकिन, बाद में उन्होंने वापसी की और उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया, साथ ही पिछले वर्ष बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान, उन्हें चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी।

एक समय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विदेश यात्राओं से जुड़ा प्रमुख चेहरा रहे राम माधव भी भाजपा नेतृत्व के कृपा- क्षेत्र से बाहर हो गए थे। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने उन्हें अपनी केन्द्रीय कार्यकारी परिषद में नियुक्त कर राजनीतिक रूप से पुनर्स्थापित किया था।

बांग्लादेश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और अब बांग्लादेश की धरती से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। अवामी लीग के शासनकाल में बांग्लादेश ने चरमपंथी तत्वों पर नियंत्रण रखने और उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए थे।

अधिकांश हमले हिंदू परिवारों की संपत्तियों को निशाना बनाकर किए गए हैं। इनमें से कई परिवार शिक्षित और पेशेवर वर्ग से हैं और उन्होंने देश में अच्छी-खासी संपत्ति अर्जित की है। कुछ सफल व्यवसायी भी हैं, जिनकी संपत्तियों को विशेष रूप से निशाना बनाया गया है। कृषक परिवारों के मामले में उनकी भूमि पर हमले किए जा रहे हैं और उन्हें अपनी जमीन से वंचित किया जा रहा है। स्थानीय जमात के तत्वों ने हिंदू संपत्तियों पर इन हमलों को बढ़ावा दिया है और यदि शीघ्र कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो उनकी स्थिति और भी खराब हो जाएगी। इस बीच हिंदुओं ने एक राजनीतिक दल का गठन किया है और वे संघर्ष करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाहरी प्रभावी सहायता और भारत से ठोस व सकारात्मक समर्थन के बिना उनकी किस्मत लगभग तय मानी जा रही है। वे अकेले दम पर अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की स्थिति में कोई बड़ा बदलाव लाने में सक्षम नहीं होंगे।

बांग्लादेश के हिंदुओं के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है-क्या भारत ने उन्हें त्याग दिया है और हाथ खड़े कर दिए हैं?

या फिर यह चुप्पी किसी ऐसे कदम की भूमिका है, जो घिरे हुए अल्पसंख्यकों की मदद के लिए उठाया जाएगा?

वायुसेना के ट्रेनी विमान की प्रयागराज में इमरजेंसी लैंडिंग

प्रयागराज, 21 जनवरी। शहर में बुधवार दोपहर एक बड़ा विमान हादसा टल गया। भारतीय वायु सेना का एक टू-सीटर माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट तकनीकी खराबी के कारण अनियंत्रित हो गया।

केपी कॉलेज के पीछे जलकुंभी से भरे एक तालाब में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस पूरे घटनाक्रम में जान-माल का कोई नुकसान नहीं हुआ।

माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट एम-116 ने सुबह करीब 11:30 बजे बमरौली एयरफोर्स स्टेशन (29वीं विंग) से नियमित उड़ान भरी। इसे ग्रुप कैप्टन जेके पांडेय और ग्रुप कैप्टन प्रवीण अग्रवाल संचालित कर रहे थे।

जोधपुर की कुख्यात गैंग का सरगना राजू पीलवा गिरफ्तार

हार्डकोर अपराधी राजूराम पर 25 हजार का ईनाम घोषित था तथा वह लंबे समय से फरार चल रहा था

जोधपुर, 21 जनवरी (कासं)। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जोधपुर जिले की कुख्यात 007 गैंग के मुख्य सरगना, हार्डकोर अपराधी एवं पुलिस थाना लोहावट के हिस्ट्रीशीटर राजूराम उर्फ राजू पीलवा को दस्तयाब कर लिया है। आरोपी पर 25 हजार का इनाम घोषित था और वह लंबे समय से फरार चल रहा था। पकड़े जाने के समय यह अपराधी भक्ति की आड़ लेने की फिराक में था और सांवरिया सेठ मंदिर दर्शन करने की योजना बना रहा था।

एडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि एजीटीएफ के कांस्टेबल सुनील को मिली सूचना की पुष्टि के बाद तुरंत कार्रवाई की गई। एसपी ज्ञानचंद यादव एवं एएसपी नरोत्तम लाल वर्मा के सुपरविज़न तथा डीएसपी फूलचंद टेलर और एएसआई राकेश जाखड़ के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। मंगलवार को राजू पीलवा जोधपुर के शताब्दी सर्किल चौराहे पर अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही मुखबिर ने एजीटीएफ कांस्टेबल सुनील को सूचना दी कि हम सांवरिया सेठ जा रहे हैं और राजू पीलवा भी हमारे साथ चलने की बात कह रहा है तथा वह इस वक्त शताब्दी सर्किल पर खड़ा है, वैसे ही एजीटीएफ की टीम ने जाल बिछा दिया और राजू पीलवा को दबोच लिया।

एडीजी एमएन ने बताया कि राजू मांजू द्वारा गठित 007 गैंग का वर्तमान में मुख्य सरगना राजू पीलवा ही था। आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास, फायरिंग, अवैध हथियार एवं मादक पदार्थ तस्करी सहित, कुल 48 गंभीर

- पुख्ता सूचना पर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम ने सांवरिया सेठ मंदिर जाने की तैयारी कर रहे हिस्ट्रीशीटर राजूराम को जोधपुर के शताब्दी चौराहे से गिरफ्तार किया।

प्रकरण दर्ज हैं। फरारी के दौरान भी वह कई अपराधों को अंजाम दे रहा था।

इस मामले में उसे फरार इनामी घोषित करने का आधार श्रवण कुमार पुत्र भलूराम विश्नोई निवासी फतेहसागर तहसील लोहावट की रिपोर्ट थी। श्रवण कुमार ने 11 अक्टूबर 2025 को थाना लोहावट में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि आरोपी राजूराम उस पर डोडा तस्करी की मुखबिरी करने का झूठा आरोप लगाकर लगातार धमकियां दे रहा था। 10 अक्टूबर को शाम करीब 4 बजे, जब परिवादी अपनी कैम्पर गाड़ी से पीलवा गांव की ओर जा रहा था, तब फतेहसागर पंचायत के पास आरोपी राजूराम, उसके भाई मदन सहित, 15-16 लोगों ने चार वाहनों के साथ रास्ता रोक लिया। आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग की, गाड़ी को टक्कर मारी, पीछा कर दोबारा गोलियां चलाईं, जिसमें एक गोली परिवादी के घुटने को छूते हुए पेट को चीरती हुई निकल गई। इसके बाद आरोपियों ने गाड़ी में आग लगाकर उसे पूरी तरह जला दिया।

राजूराम पीलवा थाना देचू पुलिस पर फायरिंग तथा चर्चित हनुमान साईं हत्याकांड का मुख्य आरोपी रहा है। इस हत्याकांड के बाद सामराउ गांव में जातीय संघर्ष भड़क उठा था, जिसमें भीड़ द्वारा करीब दो दर्जन मकानों में आग लगा दी गई थी और क्षेत्र में लंबे समय तक तनाव बना रहा था।

केरल के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी महासचिव के सी वेणुगोपाल भी मौजूद रहेंगे। सूत्रों के अनुसार केरल कांग्रेस का कहना है कि राज्य में कांग्रेस अकेले सरकार बनने की स्थिति में है। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व प्रदेश नेताओं के साथ गठबंधन पर भी विचार विमर्श करेगी।

निष्कासित अन्नाद्रमुक नेता वैथिलिंगम डीएमके में शामिल हुए

चेन्नई, 21 जनवरी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों से पहले बुधवार को निष्कासित अन्नाद्रमुक नेता आर वैथिलिंगम ने पाला बदलते हुए ओ पनीर सेल्वम (ओपीएस) का खेमा छोड़ दिया और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर सत्तारूढ़ द्रमुक में शामिल हो गये।

अन्नाद्रमुक सरकार में दो बार के मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीर सेल्वम के वफादार वैथिलिंगम ने तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष एम अप्पावु से मिलकर विधायक पद से इस्तीफा दे दिया।

कल्याण ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हो गई है कि क्या यह नागरिक निकाय में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सत्ता से बाहर रखने की एक कोशिश है।

शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को समर्थन देने के मनसे के फैसले ने न केवल भाजपा, बल्कि शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे को भी हैरान कर दिया है।

नितिन नबीन को राज्यसभा सदस्य ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विधायक रह चुके हैं और बांकीपुर सीट से लगातार चार बार जीत दर्ज कर चुके हैं।

और जब तक वे बिहार विधानसभा के सदस्य हैं, उन्हें सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेना होगा, हालांकि यह दोहरी भूमिका उनके लगातार व्यस्तता भरे कार्यक्रम में फिट नहीं बैठ सकती।

लेकिन इस मामले को नितिन नबीन को राज्यसभा में भेजकर संतुलित किया जा सकता है, जिससे वे दिल्ली में रह सकें। उनके पूर्ववर्ती जेपी नड्डा को भी इसी तरह संसद में लाया गया था।

उनके तत्काल एजेंडे में, चुनावी राज्य बंगाल का दौरा शामिल है। बंगाल हाल के वर्षों में भाजपा के सामने सबसे बड़ी और संभवत: सबसे कठिन चुनावी चुनौती माना जा रहा है। ज्ञातव्य है कि भाजपा यहां तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ लोकसभा तथा विधानसभा चुनावों में लगातार तीन बार हार चुकी है।

नबीन का राज्यसभा सदस्य बनना अप्रैल तक संभव हो सकता है। उस समय बिहार से राज्यसभा की पांच सीटें खाली होंगी और संख्या के हिसाब से

- पर, वर्तमान में बिहार की स्थिति पर भाजपा की पूरी पकड़ है। अतः, नितिन नबीन को बिहार में विधानसभा सदस्य बनाए रखने की कोई राजनीतिक विवशता नहीं, भाजपा क्या मैसेज देना चाहती, बिहार की जनता को, केवल यह ही निर्णायक होगा, इस संदर्भ में।

भाजपा को उनमें से दो सीटें मिलना तय है। दो सीटें नीतीश कुमार की जदयू को मिलेंगी।

और अगर भाजपा जोर लगाए तो वह पांचवीं सीट भी हासिल कर सकती है।

और अगर बिहार से नामांकन संभव नहीं हुआ, तो इस वर्ष राज्यसभा की 30 अन्य सीटें भी खाली हो रही हैं, जिनमें से अधिकांश सीटों पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही है। इसका मतलब यह है कि भाजपा के इतिहास के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन उच्च सदन में किसी अन्य राज्य का प्रतिनिधित्व भी कर सकते हैं। लेकिन, भाजपा के शीर्ष सूत्रों का कहना है कि ऐसा होना जरूरी नहीं है।

सूत्रों ने कहा इसकी मिसाल मौजूद है। वर्ष 2013 में अमित शाह को भाजपा का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था और अगले वर्ष उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उस समय वे विधायक थे। उन्होंने गुजरात की नारणपुरा सीट पर भारी अंतर से जीत दर्ज की थी, और इसलिए वे राज्य के विधायक बने रहे तथा उन्होंने कई बार गुजरात विधानसभा की कार्यवाही में भी हिस्सा लिया। वर्ष 2017 में जाकर उन्हें राज्यसभा में लाया गया।

और 2019 में वे गांधीनगर से लोकसभा सांसद चुने गए।

लेकिन, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दोनों मामलों में समानता पूरी तरह नहीं है।

शाह विधायक इसलिए बने रहे, ताकि वे गुजरात में भाजपा की संगठनात्मक ताकत पर नजर रख सकें।

यह उस समय जरूरी था, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद पार्टी की राज्य इकाई संक्रमण के दौर से गुजर रही थी। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों ने नरेन्द्र मोदी और अमित शाह को दिल्ली पहुंचा दिया था। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए भी गुजरात में शाह की मौजूदगी आवश्यक थी। इस हिसाब से बिहार सुरक्षित है।

अंतरिक्ष ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लिया। अपने करियर के दौरान विलयम्स ने कुल 608 दिन अंतरिक्ष में बिताए और वे अंतरिक्ष में समय बिताने के मामले में विश्व में दूसरे नंबर की नासा अंतरिक्षयात्री हैं।

नासा के प्रशासक जारेड आइजैकमैन ने कहा, "सुनी विलियम्स मानव अंतरिक्ष उड़ान में एक मार्गदर्शक रही हैं।" आइजैकमैन ने अंतरिक्ष स्टेशन पर उनके नेतृत्व और चंद्रमा के लिए भविष्य की आर्टेमिस मिशनों तथा मंगल के मिशनों के लिए आवश्यक विज्ञान और तकनीक को आगे बढ़ाने में उनके योगदान की प्रशंसा की।

कर्नाटक में राज्यपाल का विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करने से इन्कार

बंगलूरू, 21 जनवरी। केरल और तमिलनाडु के बाद अब कर्नाटक में राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच विवाद खड़ा हो गया है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 22 जनवरी को राज्य विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करने से इनकार कर दिया है। इससे पहले तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि मंगलवार को विधानसभा में अपना उद्घाटन भाषण देने से पहले ही बाहर चले गए थे। उन्होंने राष्ट्रगान के प्रति अनादर की भावना व्यक्त करते हुए निराशा जताई थी। वहीं केरल में मंगलवार को तब विवाद उत्पन्न हो गया, जब मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने विधानसभा में राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर के संबोधन समाप्त करने के तुरंत बाद आरोप लगाया था कि उन्होंने राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नीतिगत भाषण को पूरी तरह नहीं पढ़ा। कर्नाटक विधानसभा का संयुक्त सत्र 22 से 31 जनवरी तक प्रस्तावित है।

गुरु से भरे हुए ट्रंप ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ईरान पर भी बड़े काम कर सकते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि आप ग्रीनलैंड पर क्या कर रहे हैं। आइए कुछ महान निर्माण करने की कोशिश करें। मैं दावोस के बाद गुरुवार दोपहर पेरिस में एक जी-7 बैठक आयोजित कर सकता हूं। इसके इतर, में यूक्रेनियों, डेनमार्क, सीरिया और रूस को भी आमंत्रित कर सकता हूं। गुरुवार को अमेरिका लौटने से पहले पेरिस में हम साथ में रात्रिभोज करें।"

इसके अलावा, जब ट्रंप से पूछा गया कि ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए वे कितनी दूर तक जाने को तैयार हैं, तो उन्होंने कहा, "आपको पता चल जाएगा।"

इसी बीच, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयेन ने आज फिर दोहराया कि सुरक्षा कारणों से अतिरिक्त टैरिफ की धमकी देना पूरी तरह गलत है।

यूरोपीय संसद में अपने भाषण के दौरान वॉन डर लेयेन ने कहा कि "हम एक चौराहे पर खड़े हैं। यूरोप संवाद और समाधान को प्राथमिकता देता है, लेकिन हम आवश्यकता पड़ने पर एकजुटता, तत्परता और दृढ़ संकल्प के साथ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।"

डॉनल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि यूरोप के देश ग्रीनलैंड को हासिल करने की उनकी कोशिशों में बाधा डालते हैं, तो वे 1 फरवरी से उन पर अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने नाटो के सहयोगी डेनमार्क से ग्रीनलैंड पर नियंत्रण पाने की अपनी मुहिम तेज कर दी है, जिससे यूरोपीय संघ संभावित जवाबी कदमों पर विचार कर रहा है।

अपने संबोधन में यूरोपियन आयोग प्रमुख ने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में आए बदलाव को स्वीकार करते हुए कहा कि "यह बदलाव न केवल भूचाल लाने वाला है, बल्कि स्थायी भी है। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया रॉ पावर से परिभाषित हो रही है और ऐसे में यूरोप के लिए "स्वतंत्रता की दिशा में अपनी कोशिशों को तेज करना" और शक्ति के नए साधन हासिल करना अनिवार्य है।

उन्होंने कहा, "वैश्विक बदलाव का यह क्षण खतरों से भरा हुआ है। और यूरोप को और भी तेजी से बदलने के लिए तैयार रहना होगा-अपने भविष्य के लिए अधिक स्वतंत्र बनने के लिए।"

वॉन डर लेयेन ने यह भी कहा कि यूरोपीय संघ ने ट्रंप की टैरिफ धमकियों पर अपनी प्रतिक्रिया पर चर्चा करने के लिए कल एक बैठक बुलाई है।

इसी से जुड़े एक घटनाक्रम में, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि सहयोगी देशों के खिलाफ टैरिफ का इस्तेमाल "पूरी तरह गलत" है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आर्कटिक द्वीप ग्रीनलैंड वहां के लोगों और डेनमार्क का है और यह अधिकार "मौलिक" है।

स्टारमर ने ट्रंप की टैरिफ धमकियों से पैदा हुई अंतर्राष्ट्रीय उथल-पुथल के बीच मजबूत गठबंधनों को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया, साथ ही वॉशिंगटन के साथ ब्रिटेन की साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई।

स्टारमर ने कहा कि इतने गंभीर मामलों को सहयोगियों के बीच शांतिपूर्ण संवाद के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रीनलैंड की सुरक्षा महत्वपूर्ण है और जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक में नए समुद्री मार्ग खुलने तथा रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ने के साथ इसका महत्व और बढ़ेगा।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908